दौरान कितने इस्पात का निर्यात किया जायेगा ; और

(ख) नई औद्योगिक नीति का इस्पात-उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इस समय वर्ष 1991-92 के दौरान भारत में परिसज्जित इस्पात का कुल उत्पादन 145.5 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष के दौरान एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा 3.5 लाख टन परिसज्जित इस्पात का निर्यात किये जाने का अनुमान है।

(ख) नई औद्योगिक नीति में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन अनिवार्य लाइसेंसिंग के उपबन्ध से लोहा और इस्पात उद्योग को छूट दे दी गयी है। इससे और अन्य उदार उपायों से इस्पात उद्योग में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

लौह और इस्पात उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

666. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात तथा लौह उत्पादों के मूल्यों में 1 जनवरी, 1990 से अब तक अनेक बार वृद्धि की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान की गयी मूल्य वृद्धि का वर्षवार/माहवार ब्यौरा क्या है और उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार को कितना लाभ या हानि हुई ;

(ग) घाटे और मुनाफे में चल रहे लौह उद्योगों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों/उपक्रमों के नाम और उनके उत्पादन क्षेत्रों का विवरण क्या है; और

(घ) घाटे में चल रही औद्योगिक इकाइयों के सुधार और उनमें कार्यरत कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने के उद्देश्य से उनके आधुनिकीकरण के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1-1-1990 के बाद संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निम्नलिखित मूल्य वृद्धियों की घोषणा की गई थी :—

20-3-1990	उत्पाद शुल्क दरों में संशोधन के कारण लगभग 1.5% की औसतन वृद्धि।
19-9-1990	आदानों की लागत में वृद्धि को और इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि (ई जी ई ए एफ) की वृद्धि को पूरा करने के लिए आधारभूत मूल्य में औसतन 5% की वृद्धि।
25-9-1990	आकार/सेक्शन/क्वालिटी, "एक्सट्राज" आधार मूल्यों में सामान्य वृद्धि।
25-7-1991	उत्पाद शुल्क पर अधिभार में वृद्धि के कारण इस्पात पर 36 रु० प्रति टन और कच्चे लोहे पर 15 रु० प्रति टन की औसतन वृद्धि।
1-9-1991	रेल भाड़े में वृद्धि के कारण इस्पात पर 90 रु० प्रति टन तथा कच्चे लोहे पर 60 रु० प्रति टन की वृद्धि।

उत्पाद शुल्क में वृद्धि किए जाने के कारण मूल्य वृद्धि से उसी सीमा तक सरकार के उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि हुई।

माल भाड़े की दरों में वृद्धि से रेलवे के राजस्व में वृद्धि हुई।

(ग) निजी उद्योगों के लाभ/हानि का ब्यौरा इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की जिन इकाइयों को 1990–91 में हानि हुई उनमें इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) और विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (वी आई एस एल) है। 'इस्को' कच्चा लोहा, इस्पात और कास्ट आयरन, स्पन पाइपों का उत्पादन कर रहा है। वी आई एस एल इस्पात, लौह मिश्र और ढलवा लोहे का उत्पादन करता है। 1990–91 में सरकारी क्षेत्र की जिन इस्पात इकाइयों ने लाभ अर्जित किया उनमें स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (मेल) हैं। "सेल" इस्पात और कच्चे लोहे का उत्पादन करता है और "मेल" इस्पात और लौह मिश्र का उत्पादन करता है।

(घ) "सेल" के प्रमुख इस्पात संयंत्रों का या तो आधुनिकीकरण (दुर्गापुर और राउरकेला संयंत्र) किया जा रहा है या आधुनिकीकरण (बोकारो और बर्नपुर इस्पात कारखाना) करने के लिए विचार किया जा रहा है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप प्रचालन के तकनीकी आर्थिक प्राचलों में सुधार, लागत में कमी और लाभदायकता में सुधार होने की सम्भावना है।

Steel production in secondary sector

667. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the steps Government propose to take to raise the steel production in the secondary sector in the country;

(b) the amount of money likely to be spent for the purpose ; and

(c) whether the target for steel production is likely to be achieved by such measures?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) In the new Industrial Policy, the iron and steel industry has been removed from the list of industries reserved for the public sector. It has also been exempted from the requirements of compulsory licensing under the Industries (D&R) Act, 1951. Customs duty on imported scrap has been reduced from 35% to 10%. These measures are aimed at attracting sizeable private investment in the secondary steel sector and increasing production in this sector.

(b) The investment will depend on the nature and size of the projects taken up.

(c) Substantial increase in production in the secondary steel sector will help to meet the projected demand for steel in the country.

Distribution Net-work of SAIL

668. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the need to strengthen the distribution network ;

(b) if so, the steps taken by the Steel Authority of India Limited (SAIL) in this regard ;

(c) whether Government are considering a proposal for setting up some nodal stock yards in order to strengthen distribution net-work ; and

(d) if so, the names of the places where the stock yards are proposed to be set up ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) The distribution network of the integrated steel plants for the sale of iron and steel is as follows :

	Stockyards	Consignment Agency	Extension Counter
SAIL .	45	8	3
VSP .	3	15	—
IISCO .	1	5	—
TISCO .	11	23	—

SAIL has been taking action from time to time to expand its distribution network to cater to the increasing sale of iron and steel materials to larger number of consumers spread throughout the country.

As a mesures to increase handling of materials through the major stockyards, SAIL is modernising them in the same location or in alternate location in a phased manner.